

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2695
जिसका उत्तर 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....
नदियों को परस्पर जोड़ना

2695. श्री रामचरण बोहरा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में नदियों को परस्पर जोड़ने के कोई प्रस्ताव लंबित हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लंबित होने के क्या कारण हैं;
- (ग) उक्त राज्यों में नदियों और बांधों को परस्पर जोड़ने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;
- (घ) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने में किसी बाधा का सामना करना पड़ रहा है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत 14) को चिह्नित किया है। एनपीपी के अंतर्गत चिह्नित 30 संपर्क परियोजनाओं में से, सभी 30 लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई है, जबकि 24 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 8 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में दिसंबर, 2021 में केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन को विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात् केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 44,605 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित कर दिया था। केबीएलपी एनपीपी के तहत नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) वाली पहली परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित आईएलआर परियोजनाओं की राज्य-वार नवीनतम स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) से (ङ): इस महत्वपूर्ण आईएलआर कार्यक्रम को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बनाकर परामर्शी तरीके से चलाया जा रहा है। हालांकि, जल बंटवारे आदि से संबंधित मुद्दों पर पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बनाना आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। हालांकि, आईएलआर लिंक परियोजनाओं का कार्यान्वयन आम सहमति बनाने के लिए संबंधित राज्यों पर निर्भर करता है।

“नदियों को परस्पर जोड़ना” के संबंध में दिनांक 16.03.2023 को लोकसभा में उतर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2695 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के तहत नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावों का ब्यौरा और स्थिति

क्र.सं.	नाम	नदियां	संबंधित राज्य	स्थिति
प्रायद्वीपीय घटक				
1(क)	महानदी (मणिभद्र)- गोदावरी (दोवलईस्वरम) लिंक	महानदी और गोदावरी	झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	एफआर पूर्ण
1(ख)	महानदी (बेरमुल)- गोदावरी (दोवलईस्वरम) लिंक	महानदी और गोदावरी	--वही --	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंतला) जोड़	गोदावरी और कृष्णा	ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर पूर्ण
3	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	गोदावरी और कृष्णा	--वही--	एफआर पूर्ण डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (पोलावरम)- कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	गोदावरी और कृष्णा	--वही--	एफआर पूर्ण
5	कृष्णा (अलमट्टी) -पेन्नार लिंक	कृष्णा और पेन्नार	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम)-पेन्नार लिंक	कृष्णा और पेन्नार	--वही--	एफआर पूर्ण
7	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक	कृष्णा और पेन्नार	--वही--	एफआर पूर्ण डीपीआर पूर्ण
8	पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गेंड एनीकट) लिंक	पेन्नार और कावेरी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी	एफआर पूर्ण डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई-गुंडर लिंक	कावेरी, वैगई और गुंडर	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी	डीपीआर पूर्ण
10	केन-बेतवा लिंक	केन और बेतवा	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूरी हुई। कार्यान्वयन शुरू हुआ।
11 (i)	पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक	पार्वती, कालीसिंध और चंबल	आम सहमति बनाने के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से परामर्श करने का अनुरोध किया गया)	एफआर पूर्ण
(ii)	संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	पार्वती, कुनो, कालीसिंध, चंबल, मेज और बनस	मध्य प्रदेश और राजस्थान	पीएफआर पूर्ण \$
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	पार, तापी और नर्मदा	महाराष्ट्र और गुजरात	डीपीआर पूर्ण
13	दमनगंगा- पिंजल लिंक	दमनगंगा और पिंजल	--वही--	डीपीआर पूर्ण
14	बेदती-वरदा लिंक	बेदती और वरदा	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
15	नेत्रावती - हेमवती लिंक	नेत्रावती और हेमवती	कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल	पीएफआर पूर्ण
16	पंजा - अचनकोविल-वैप्पार लिंक	पंजा, अचनकोविल और वैप्पार	केरल और तमिलनाडु	एफआर पूर्ण
\$ राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक का एकीकरण।				

हिमालयी घटक				
1.	मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	मानस, संकोश, तिस्ता और गंगा	भूटान और भारत (असम, पश्चिम बंगाल और बिहार)	एफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	कोसी और घाघरा	नेपाल और भारत (बिहार और उत्तर प्रदेश)	पीएफआर पूर्ण
3.	गंडक-गंगा लिंक	गंडक और गंगा	--वही--	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
4.	घाघरा-यमुना लिंक	घाघरा और यमुना	--वही--	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
5.	सारदा-यमुना लिंक	सारदा और यमुना	नेपाल और भारत (बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान)	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	यमुना और सुकरी	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	साबरमती	--वही--	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	गंगा और सोन	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	सोन और बटुआ	बिहार और झारखंड	पीएफआर पूर्ण
10.	गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक	गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
11.	सुबर्णरेखा-महानदी लिंक	सुबर्णरेखा और महानदी	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण
12.	कोसी-मेची लिंक	कोसी और मेची	नेपाल और भारत (बिहार और पश्चिम बंगाल)	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का)-सुंदरबन लिंक	गंगा और इच्छामती	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
14.	जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	मानस, तिस्ता और गंगा	असम, बिहार और पश्चिम बंगाल	परित्यक्त

- पीएफआर- पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट
- एफआर- व्यवहार्यता रिपोर्ट
- डीपीआर- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
